

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): At about 3.47 hrs. on 28th February, 1965, while train No. 24 Dn. Siliguri—Manihari Ghat Passenger was running between Sonaili and Dandkhora stations on the Katihar—Siliguri Metre Gauge section of Northeast Frontier Railway, fire was noticed in a third class-cum-postal van coach, the third vehicle from the engine.

The train was brought to a stop and efforts were made to extinguish the fire with the available fire extinguishers on the train.

Since the fire could not be extinguished with the available fire extinguishers, the train engine with the first three coaches was taken to Dandkhora where the fire was extinguished and the affected coach detached. Thereafter the rear portion was brought to Dandkhora and the train left after a detention of over one hour.

Three passengers sustained slight injuries. First aid was rendered to them on the spot and they were allowed to proceed on their journey.

The cause is under investigation and an enquiry has been ordered.

Shri Madhu Limaye: Whether the chain was alright and it was pulled?

Dr. Ram Subhag Singh: Yes, it was pulled and the chain was alright. But we can't say definitely at present that how far this published news is correct.

Shri Madhu Limaye: Whether some order has been given that this chain system may be stopped at this line?

Dr. Ram Subhag Singh: There is no such order. The whole matter is being inquired into. We will be getting the report within 20—25 days.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी

MOTION ON PRESIDENT'S ADDRESS—Contd.

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधान मंत्री ।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): इस प्रस्ताव पर चर्चा लम्बी हो गयी है। लगभग सभी सदस्यों ने जो इस पर बोले भाषा समस्या की गम्भीरता से प्रभावित थे। मद्रास राज्य में हिंसक कारनामों हुए सबने उसका उल्लेख किया। भयानक कारनामों हो गये और कई लोग मर गये, लूटमार हुई मकान जला दिये गये। सब कुछ बड़ा दुःखदायी और खेदजनक है।

श्री हीरेन मुकर्जी का सुझाव है कि हमें सब कुछ भूल कर एक नया अध्याय आरम्भ करना चाहिए। विद्यार्थी ने वक्तो जोश में आकर गलत बातें कर दी हैं। परन्तु यह बात भी स्पष्ट है कि इन सब घटनाओं में समाज विरोधी तत्वों का भी बहुत बड़ा हाथ है। यदि उन्हें रोका न गया और उन्हें ऐसे ही लूट मार और हिंसा करने को छूट दे दी गयी तो समस्त समाज में शान्तिमय जीवन असम्भव हो जायेगा। अतः यह बड़ा ही जरूरी है कि उनके मामलों में कानून के अनुसार कार्यवाही की जाय। मैंने इस मामले में मुख्य मंत्रियों से बात की है और वर्तमान स्थिति में जो कुछ सम्भव है वह किया जायेगा।

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

जहां तक इस मामले के विभिन्न पहलुओं का सम्बन्ध है, स्वर्गीय पंडित नेहरू द्वारा दिए गए आशवासनों का बिना संकोच के तथा एकमत से स्वागत किया जायेगा। जैसा कि सभा को विदित है, भाषा के सवाल पर संसद तथा संसद से बाहर चर्चा की जा चुकी है तथा कई मामले उठाए जा चुके हैं जैसा कि राज भाषा अधिनियम में संशोधन, त्रिभाषीय सूत्र, परीक्षा के लिये माध्यम तथा सेवाओं में न्यायपूर्ण भाग, उन सब बातों के विषय में मेरे अपने निश्चित तथा स्पष्ट विचार हैं। परन्तु मैं इस समय अपनी निजी राय को व्यक्त नहीं करना चाहता। मेरा विचार है कि मुझे तथा इस सभा को अपने विचार कुछ समय बाद व्यक्त करना चाहिये जब कि सारे मामले का सावधानी से अध्ययन और परीक्षण किया जाय।

एक बात बड़ी स्पष्ट है वह यह कि हिन्दी को लादा कहीं नहीं जा रहा। हिन्दी के लादे जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। जो लोग हिन्दी नहीं जानते वे अंग्रेजी में अपना कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार ही प्रादेशिक भाषाओं का प्रश्न है। वह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम उन्हें पूर्ण प्रोत्साहन देना चाहते हैं और हमारी इच्छा है कि सभी राज्य सरकारें प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करें। प्रादेशिक भाषाओं द्वारा हिन्दी को किसी प्रकार की हानि पहुंचाये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

Shri Madhu Limaye: The Prime Minister should speak in national language.

Mr. Speaker: Now you should hear.

श्री लाल बहादुर शास्त्री : बहूत से राज्यों ने प्रादेशिक भाषा को अपनी राजभाषा बना लिया है। हम उन्हें पूरी सहायता दे रहे हैं। वैसे भी इस मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

Dr. Ram Manohar Lohia: When there is arrangement of translation, why you impose English on you.

Shri Lal Bahadur Shastri: I may have spoken in Hindi, but some members wanted that I should speak in English.

Shri Ram Sewak Yadav: Many members desire, as the arrangement of translation is there, you should speak in your own mother tongue.

Dr. Ram Manohar Lohia: You will continue with English for all times.

Mr. Speaker: I will request the honourable members not to interrupt. Any members can make his own choice and can speak either in Hindi or in English. Arrangement of translation is there. We should maintain the decorum of the House.

Shri Lal Bahadur Shastri: At present, I am speaking in English and will speak in English. In future I will also speak in Hindi.

Mr. Speaker: You can speak as you like.

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भाषा की समस्या को देखना चाहिये। देश की सारी भाषायें तो राजभाषायें बन नहीं सकतीं। अतः मेरा निवेदन है, हमें सारे मामलों पर प्राकृतिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। यह अत्यावश्यक है कि देश में एक सम्पर्क या साझी भाषा ही अन्यथा देश विभिन्न भागों में बट जायगा और उसका विघटन हो जायगा। उस कारण से हिन्दी को संघ सरकार की राज भाषा माना गया या उसे ऐसा माना जाना चाहिये। साथ ही हमें

ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिये जिससे देश की अखण्डता टूटने के बजाय कायम रहे। हमें इस मामले में मन्दगति से चलना चाहिये। हमें इस बात की स्वेच्छापूर्ण ढंग से सीखने पर कोई आपत्ति नहीं की जायगी। फिर भी जो व्यक्ति हिन्दी नहीं जानते, उनकी नियुक्ति तथा पदोन्नति में कोई अड़चन नहीं आयेगी।

जहाँ तक खाद्य का संबंध है, अब यह कहा जा सकता है कि बहुत खराब स्थिति का अन्त हो चुका है। परन्तु हमें अभी कठिनाइयों का सामना है। चावल के उत्पादन संबंधी आंकड़े कोई 39 करोड़ टन है और हमें गेहूँ की बड़ी फसल की आशा है। कुछ समय के लिए स्टोक मार्केट में उपलब्ध है तथा हम समाहार का कार्य कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि खाद्यान्न के आयात को कम किया जाय परन्तु कुछ समय तक आयात के बिना हम अच्छे "बफर स्टोक" को कायम नहीं कर सकेंगे। आयात और स्वदेशी उत्पादन की सहायता से हमारे लिए कमी के समय की कठिनाइयों पर काबू पा लेना सम्भव हो सकेगा। उत्पादन की दृष्टि से ही हमने योजना में सबसे अधिक जोर कृषि पर ही रखा है। शायद मार्च का महीना कुछ कठिन निकले। हमें तनिक सज़बूज से काम लेना होगा। अप्रैल से नयी फसल मंडी में आ जायेगी।

कृषि उत्पादन की ओर राज्य सरकारों को अधिक ध्यान देना चाहिये क्योंकि यह उनका उत्तरदायित्व है। वह इस ओर पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यदि कृषि उत्पादन में वृद्धि न हुई तो उनको और उनके लोगों के लिये यह बहुत हानिकारक होगा। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक खेत की जांच होनी चाहिये कि वहाँ उत्पादन बढ़ा है कि नहीं और यदि नहीं बढ़ा तो उसका बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। बढ़ते हुये मूल्यों के कारण हम बहुत चिन्तित हैं। कुछ दिन हुये वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे वित्तीय उपाय किये हैं जिनसे मुझे आशा है कि मूल्य अधिक नहीं बढ़ेंगे। बजट प्रस्तावों के आधार पर हमारी अर्थ व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। इन प्रस्तावों से सर्वसाधारण को कुछ हद तक सहायता मिली है। और हमें इस प्रकार का बजट आगे भी जारी रखना पड़ेगा। इस वर्ष का बजट, एक संतुलित बजट है और इसमें देश को गरीब जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। आय और जीवन यापन स्तर में असमता को कम करने की उद्देश्यपूर्ति के लिये नागर सम्पत्ति पर कर लगाये गये हैं। सरकारी क्षेत्र में अधिक कारखाने और उद्योग खोलने से कुछ लोगों के हाथ में धन इकट्ठा नहीं होता और लोगों को रोजगार भी मिलता है। हमने सरकारी क्षेत्र में आधार और भारी उद्योग आरम्भ किये हैं। यह एकदम लाभ नहीं देते हैं। परन्तु जहाँ कहीं वह स्थापित किये गये हैं उन्होंने मुख्य और सहायक उद्योगों को सहायता दी है।

श्री रंगा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में घाटे के बजट का निर्देशन किया है। वित्त मंत्री ने प्रतिरक्षा की भारी मांगों के बावजूद सन्तुलित बजट प्रस्तुत किया है। मैं श्री रंगा से सहमत नहीं हूँ कि उत्पादन नहीं बढ़ेगा। तीसरी योजना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि दोनों योजनाओं से अधिक रही है।

श्री मुकर्जी ने कहा था कि विदेशी पूंजी के पक्ष में हमारी नीति में भारी परिवर्तन हुआ है। इस सम्बन्ध में 6 अप्रैल, 1949 को संसद में पंडित जवाहर लाल जी के भाषण से उद्धरण देना चाहता हूँ इसमें उन्होंने विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में नीति को बनाया था। उसी नीति का हम अभी तक पालन कर रहे हैं।

"किसी भी उपक्रम का स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण भारतीय हाथों में होना चाहिये। यदि राष्ट्रीय हित में हुआ तो विदेशी पूंजी का किसी उपक्रम पर सीमित अवधि के लिये नियंत्रण

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। विदेशी पूंजी का उपयोग हम न केवल इसलिये कर रहे हैं कि भारतीय पूंजी देश के विकास के लिये पर्याप्त नहीं है, बल्कि कुछ मामलों में वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक ज्ञान केवल विदेशी पूंजी के साथ ही प्राप्त हो सकता है।”

जब भी हम किसी विदेशी संस्था से सहयोग करते हैं तो अधिकांश शेयर अपने पास रखते हैं। कुछ मामलों में जहां तकनीकी ज्ञान हमारे पास नहीं होता अधिकांश शेयर रखना सम्भव नहीं है। परन्तु जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र का सम्बन्ध है हम केवल आधार और भारी उद्योगों के लिये ऐसे सहयोग स्वीकार करते हैं। यदि किसी विदेशी संस्था को हम अधिकतम शेयर दे भी देते हैं तो वह भी सीमित अवधि के लिये दिये जाते हैं। उस अवधि के बाद उनको वह शेयर भारतीय सहयोगी को बेचने पड़ते हैं।

हमारा उद्देश्य समाजवाद है और हम इसे विभिन्न योजनाओं द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। यह आयोजना का कार्य बहुत कठिन है क्योंकि जनता की आवश्यकतायें बहुत अधिक हैं। यदि इन आवश्यकताओं को देखते हुए योजना बनाई जाय तो वह इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके लिये संसाधनों को ढूंढना बहुत कठिन हो जाता है। हमें योजना को वास्तविक संसाधनों को देखते हुए तैयार करना चाहिए।

दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। हमें अपने संसाधनों की स्थिति को ध्यानपूर्वक जांच करनी चाहिये। दूसरे उत्पादन विनियोजन के अनुसार होना चाहिये। यदि विनियोजन अधिक हुआ और उत्पादन कम हुआ, तो इससे स्फीति होगी। योजना को प्रभावकारी रूप से और शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये हमें चार चीजों का ध्यान रखना चाहिये। सबसे पहले प्रत्येक परियोजना के सविस्तार व्यौरे सहित तैयार करना चाहिये : दूसरे प्रत्येक एकक का समय और परिव्यय नियत होना चाहिये। तीसरे, प्रगति पर ध्यान रखने की भी कोई व्यवस्था होनी चाहिये। चौथे, चौथी योजना की परियोजनाओं पर प्रारम्भिक कार्य इसी वर्ष शुरू हो जाना चाहिये। हमें कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये अधिक सुविधायें देनी चाहियें। यदि हम इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो हमारी योजना सफल हो सकेगी।

अपनी वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में हम अपनी आधार नीतियों पर चल रहे हैं। हम प्रत्येक देश से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना चाहते हैं। विकासी देश होने के कारण हम चाहते हैं कि विश्व में शांति रहे। जिन देशों ने हाल ही में स्वतंत्रता प्राप्त की है, सब पिछड़े हुए हैं, विशेषतया आर्थिक रूप से; यह सब देश विश्व की शांति का भंग होना पसन्द नहीं करेंगे। यदि हमारी विचारधारा अन्य देशों से भिन्न है फिर भी उनके साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने में हमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। इसलिये नटस्थता और सह-अस्तित्व की नीति हमारे लिये बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है।

विएतनाम की स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है। हाल ही में हमने भारत सरकार की ओर से एक वक्तव्य जारी किया था जिसमें हमने मुझसे दिया था कि युद्ध एकदम बन्द हो जाना चाहिये और जेनेवा की तरह का एक सम्मेलन बुलाया जाना चाहिये। हमने अमरीका और रूस की सरकारों को भी लिखा है और कुछ अन्य तटस्थ देशों को भी लिखा है। उन्होंने हमारे विचार कर समर्थन किया है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मलेशिया और इण्डोनेशिया के झगड़े के प्रति सरकार का क्या रवैया है? इस सम्बन्ध में अभिभाषण में भी कुछ नहीं कहा गया।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मलेशिया और इण्डोनेशिया के सम्बन्ध में हमारा विचार यह है कि दोनों देशों में कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिये। और यह प्रसन्नता का विषय है कि कुछ देश दोनों देशों में शांतिपूर्ण वार्ता करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन में, मुझे आशा है, तटस्थता, सह-अस्तित्व, निःशस्त्रीकरण और शांति की नीतियों का समर्थन किया जायगा। और मुझे आशा है कि यह सम्मेलन अफ्रीकी-एशियाई एकता को सुदृढ़ करेगा।

चीन ने अणुबम का विस्फोट किया है; परन्तु हम इसका अनुकरण नहीं करना चाहते और हमने यह निश्चय किया है कि हम अणु बम नहीं बनायेंगे। तथापि, शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिये हम अणु शक्ति का विकास करते रहेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : कोलम्बो प्रस्तावों का क्या हुआ ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमने अधिक से अधिक कर दिया है; हमें इस मामले में और कुछ नहीं कहना क्योंकि यह कोलम्बो देशों का प्रस्ताव है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मेरे विचार में यह उपयुक्त उत्तर नहीं है। 14 नवम्बर, 1962 को जो संकल्प सभा ने पारित किया था उसके अनुसार जिस क्षेत्र पर चीन, ने कब्जा किया था उसको खाली करवाना प्रधान मंत्री का दायित्व है। यह उनका देश और संसद् के प्रति पहला वचन था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार क्या कदम उठा रही है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं वचनबद्ध हूँ। परन्तु माननीय सदस्य, मुझे आशा है, यह नहीं चाहते कि आज ही हम चीन पर आक्रमण कर दें।

श्री नाथ पाई : हम चाहते हैं कि हमारी धरती को मुक्त कराया जाय।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमें अपनी तैयारी भी देखनी है और यह भी देखना है कि समय उपयुक्त है कि नहीं। बिना समस्या के पहलुओं पर विचार किये हम ऐसा कदम नहीं उठा सकते।

श्री रंगा (चित्तूर) : आपके भाषण में देश की धरती को मुक्त कराने का लेशमात्र भी निश्चय नहीं है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यदि माननीय सदस्य सोचते हैं कि मैं कल ही चीन पर आक्रमण कर दूंगा तो मुझे खेद है....

श्री नाथ पाई : प्रधान मंत्री ने दो बार कहा है कि हम उनसे चीन पर हमला करने के लिये कह रहे हैं। यदि हम नेफा या लद्दाख में जायें तो क्या यह चीन पर आक्रमण होगा। यदि हम अपनी धरती पर जायें तो शत्रु के कब्जे में है तो यह कहना कि यह आक्रमण है सच्चाई का उत्खंडन है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जहां तक नेफा और लदाख का सम्बन्ध हम वहीं हैं परन्तु और कदम उठाना

श्री दाजी ने अभी कहा कि मैं दक्षिणपन्थी हो गया हूं। साम्यवादी दल में भी दो वर्ग हैं, दक्षिणपन्थी और वामपन्थी। हम बायें या दाएं जाने के बजाये आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दल में मतभेद है और अलग अलग लोगों द्वारा भिन्न भिन्न वक्तव्य दिये जा रहे हैं। परन्तु इसके लिये कांग्रेस को ही दोष नहीं दिया जा सकता। साम्यवादी दल में भी फूट है और स्वतंत्रता दल में भी भिन्न भिन्न मत व्यक्त किये जाते हैं। समाजवादी दल में भी मतभेद है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : परन्तु जब कोई भी दो मंत्री एक विषय पर सहमत न हों तो बात बहुत गंभीर हो जाती है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह सच नहीं है।

कांग्रेस 1920 से ही इसी प्रकार की है। डा० लोहिया भी जब कांग्रेस में थे तो इनका बहुमत से भिन्न मत होता था। कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन है और यदि इसमें भिन्न मत व्यक्त किये जाते हैं तो इसे गंभीरतापूर्वक नहीं लेना चाहिये। पिछले कुछ महीनों में लोगों ने कांग्रेस में अपना विश्वास दिखाया है, जैसाकि उप-चुनावों और पंचायत के चुनावों से स्पष्ट है।

इस समय राष्ट्रीय एकता की बहुत आवश्यकता है। हाल ही की घटनाओं में जिन लोगों ने उत्तेजनात्मक कार्यवाहियां की हैं वह देश के मित्र नहीं थे। उन्होंने उन लोगों का वर्षों का कार्य जिन्होंने देश की स्वतंत्रता और एकता के लिये अपना बलिदान दे दिया, कुछ ही दिनों में मिट्टी में मिला दिया। संसद्-सदस्य किसी एक क्षेत्र के नहीं अपितु पूरे देश के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने देश की अखण्डता बनाये रखने के लिये शपथ ली हुई है।

लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था में वाक्-स्वातन्त्र्य होना चाहिये। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि अनुशासन नहीं होना चाहिये। दल में अनुशासन होना चाहिये। मंत्रिमंडल में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिये और मंत्रिमंडल के सदस्यों को एक आवाज से बोलना चाहिये। मेरे कार्यक्रम और नीतियां बिल्कुल स्पष्ट हैं। मैं जानता हूं कि आधार सिद्धांत क्या हैं। यह सरकार, शासन कुछ ऐसी परम्पराओं के अनुसार चलाना चाहती है जो लोकतन्त्र के लिये बहुत आवश्यक हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री मी० ह० मसानी का संशोधन संख्या 6 मतदान के लिये रखा गया।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 12, विपक्ष में 193

Ayes: 12; Noes: 193.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was negatived.